मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में नई तांबा खदानें

430. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ग्राम कोचेवाटी बुदबुदा में नई खदान की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोचेवाटी बुदबुदा क्षेत्र में उत्खनन के कारण कौन-कौन से गांवों के प्रभावित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या कोचेवाटी बुदबुदा तांबा खदानों से प्रभावित होने वाले ग्रामों का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमति राम दुलारी सिन्हा): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1984 में शेरपरटोला से 500 मीटर उत्तर में बुदबुदा के आस-पास के क्षेत्र का अध्ययन किया था लेकिन वहां किसी बड़े या छोटे तांबा खनिजीकरण के होने का कोई संकेत नहीं मिला ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

एच.एस.सी.एल. को बंद किया जाना

431. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एच. एस. सी. एल.) को बंद करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) एच.एस.सी.एल. के बंद होने के परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारियों और श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ग्वालियर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना

432 **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 17 मई, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 265 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनिजों पर रायल्टी की दरों का पुनर्निर्धारण

433 **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिजों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद खनिजों पर रायल्टी की दरों में नियमानुसार अपेक्षित वृद्धि अभी तक नहीं की गई जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) रायल्टी की दरों का पुनर्निर्धारण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) प्रधान

खनिजों की रायल्टी की दरों में संशोधन के प्रश्न पर विचार करके सरकार को अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार ने नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1985 में दी है। अध्ययन दल की अनुशंसाओं पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

Increase in ceilings of expenditure on cyclone relief works in Andhra Pradesh

434. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State of Andhra Pradesh Government asked the Central Government for enhancement of ceilings of expenditure in regard to November, 1984 cyclone relief works;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action the Central Government have taken on the request of the State Government and what amount of grant was released by the Central Government for the rehabilitation of the victims of the cyclone?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Yes, Sir. The Government of Andhra Pradesh requested for enhancement of the ceilings of expenditure sanctioned to the State Government in the wake of cyclone of November, 1984 by Rs. 449.60 lakhs.

(c) The request of the State Government has been considered by Government of India and it has been decided not to reopen the case as the ceilings were fixed on the basis of the report of the Central Team and recommendations of the High Level Committee on Relief thereon. An amount of Rs. 17.14 crore, has been released by Government of India for the cyclone relief works in the wake of cyclone of November, 1984 on the basis of details of expenditure received from the State Government.

Setting up of National Institute of Disaster Management

435. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government are contemplating to establish a National Institute of Disaster Management in Andhra Pradesh;

(b) if so, by when the Institution is likely to be set up;

(c) what are the recommendations of the Andhra Pradesh Government for the location of the Institute; and

(d) what action Government have taken on the recommendations of the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d) The proposal for setting up a National Institute of Disaster Management is under consideration. Besides, Andhra Pradesh the States of Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Gujarat have suggested for location of the proposed Institute in their States. A Committee has been set up to recommend the alternative sites for establishment of the proposed Institute. The recommendations of the Committee are awaited.

Colonies taken over by Municipal Corporation, Delhi in Indraprastha Extension (Part-II)

436. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the norms prescribed by the Municipal Corporation of Delhi for taking over approved colonies;

(b) the names of the approved colonies in Indraprastha Extension (Part-II), New Delhi;